शोध मंथन Vol. XV No.III July.-Sept. 2024 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

सतत् विकास लक्ष्यों एवं महिलाओं के सशक्तिकरण में पीएम उज्जवला योजनाः एक अध्ययन

प्राप्तिः .2024
स्वीकृतः 15.09.2024

67

श्रीमती निशा
शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग,
साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय,
बरेली, उत्तर प्रदेश
ईमेलः *nisha22666@gmail.com*

प्रो (डॉ.) अनामिका कौशिवा
अर्थशास्त्र विभाग,
साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय,
बरेली, उत्तर प्रदेश
ईमेलः *econanamika@gmail.com*

सारांश

सतत् विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक समावेश के संतुलित संयोजन की रणनीति पर आधारित है। बीसवीं शताब्दी में विकास के परिणामस्वरूप आज मानवता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन में ऊर्जा का प्रमुख योगदान है। भारत में महिलाएं, विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण क्षेत्र में, लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कोयला और मिट्टी के तेल जैसे ईंधन का उपयोग करती हैं। मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना शुरू की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी वितरकों में पंजीकृत होने के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता देना है। इस शोध आलेख का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की राह में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की भूमिका का अध्ययन करना और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में कितनी सहायक सिद्ध हो रही है का अध्ययन करना है।

मुख्य शब्द

ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समावेश ऊर्जा दक्षता, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

सतत् विकास का अर्थ है "वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है" (संयुक्त राष्ट्र, सतत् विकास आयोग)। यह मानव भलाई के लिए आर्थिक विकास, पर्यावरण स्थिरता और सामाजिक समावेश के संतुलित संयोजन की रणनीति पर आधारित है। यदि अर्थव्यवस्था सतत् विकास प्राप्त करना चाहती है तो उपरोक्त तीनों में से किसी का भी त्याग नहीं किया जा सकता है। बीसवीं शताब्दी में विकास पथ ने वैश्विक परिस्थिति को अस्थिरता की एक खतरनाक सीमा से आगे धकेल दिया जिसके परिणामस्वरूप पर्यावरण और मानव भलाई के लिए विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं। आज, मानवता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन के संकट का सामना कर रही है। बड़े पैमाने पर वायु और जल प्रदूषण, जंगलों पर निरंतर बढ़ती हुई मांग के कारण जैव विविधता का व्यापक नुकसान, और जीवाश्म संसाधनों की कमी हो रही है। जलवायु परिवर्तन में ऊर्जा का प्रमुख योगदान है, और यह लगभग वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लगभग 60 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है। 1990 के बाद से, वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 46 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है[8]। "जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता हानि, और प्रदूषण और अपशिष्ट का मानव–प्रेरित ट्रिपल ग्रह संकट प्रकृति को ब्रेकिंग पॉइंट पर धकेल रहा है[9]। खाद्य संसाधनों की कमी, सांस लेने वाली हवा का प्रदूषण, पेय जल संसाधन की घटती आपूर्ति और प्राकृतिक संसाधन हमारे समाज के ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। "तिहरा संकट, गरीबों, महिलाओं और आदिवासी लोगों सहित कमजोर लोगों पर सबसे अधिक भारी पड़ रहा है[10]। ऊर्जा दक्षता के लिए अक्षय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन शमन और आपदा जोखिम में कमी के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी की आवश्यकता होती है। खाद्य उत्पादन, विषेश रूप से खाना पकाने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के साथ–साथ जैव विविधता के नुकसान का एक प्रमुख कारक है। वर्ष 2021 में भी दुनिया की लगभग एक–तिहाई जनसंख्या लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कोयला और मिट्टी के तेल जैसे ईंधन का उपयोग करने वाली पारंपरिक खाना पकाने की विधियों का उपयोग करती है क्योंकि खाना पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों की कमी है। इस ऊर्जा गरीबी का अर्थ है कि दुनिया के सबसे गरीब वर्ग का स्वास्थ्य और कल्याण जोखिम में है और इसका मतलब यह भी है कि लैंगिक असमानता बनी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल घरेलू वायु प्रदूषण के कारण 3.2 लाख मौतें होती हैं[11]। घरेलू वायु प्रदूषण के कारण होने वाली तीन–चौथाई से अधिक मौतें स्ट्रोक, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज और फेफड़ों के कैंसर जैसी गैर–संचारी बीमारियों से होती हैं।

2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने गरीबी को समाप्त करने, असमानता को कम करने और 2030 तक अधिक शांतिपूर्ण, समृद्ध समाजों के निर्माण के लिए सत्रह सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपनाया। यह लक्ष्य सतत् विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करते हैं। इन पहलुओं में से सतत् विकास के लिए एक पहलू है ऊर्जा दक्षता।[12]

तीन सतत् विकास लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मुद्दे से निकटता से जुड़े हुए हैं–एसडीजी लक्ष्य पांच, लक्ष्य सात और लक्ष्य बारह। वे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक तरफ लैंगिक समानता से संबंधित हैं और दूसरी तरफ पर्यावरण क्षरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर केंद्रित हैं। एसडीजी लक्ष्य पांच "लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना" है, एसडीजी लक्ष्य सात, "सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करने" का आह्वान करता है। जलवायु परिवर्तन से निपटने और लैंगिक समानता, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सहित कई अन्य एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एसडीजी सात प्राप्त करना आवश्यक है। एसडीजी लक्ष्य बारह, 'सतत् उपभोग और उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों के सतत् प्रबंधन और कुशल उपयोग" का लक्ष्य निर्धारित करता है।[13]

भारत में समाज का एक बड़ा वर्ग, विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण भूमिहीन किसान, श्रमिक और महिलाएं आर्थिक और सामाजिक विकास में पिछड़ गए हैं। ये सामाजिक–आर्थिक विकास से सामाजिक रूप से बहिष्कृत है। सामाजिक समावेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत् सामाजिक आर्थिक असमानता और बहिष्करण को कम करने के लिए नीतियाँ पेश की जाती हैं। ये नीतियाँ समाज के वंचित वर्ग की संपत्ति, क्षमताओं और अवसरों तक पहुंच में सुधार पर जोर देते हैं। हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए रियायतें और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इन परिवारों को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। गरीबों और बहिष्कृत लोगों के उत्थान के लिए कई सरकारी नीतियाँ हैं। स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की कमी और गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में इसे वहन करने में असमर्थता सामाजिक–आर्थिक बहिष्कार का एक संकेतक है। वर्ष 2016 में देश में 16.64 करोड़ सक्रिय एलपीजी उपभोक्ता थे और इनमें से अधिकांश शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में थे गरीब परिवारों तक स्वच्छ ईंधन (एलपीजी) की पहुंच सीमित थी। महिलाएं, विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण क्षेत्र में, लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कोयला और मिट्टी के तेल जैसे ईंधन का उपयोग करने वाली पारंपरिक खाना पकाने की विधियों का उपयोग करती थी। महिलाएं समाज की रीढ़ हैं जो समाज को आगे बढ़ाने के लिए सशक्त रूप से काम करती हैं। महिलाओं के धुएं के निरंतर संपर्क में रहने के कारण बहुत–सी बीमारियां जन्म लेती हैं इससे सांस, आंख सहित कई प्रकार की बीमारी होती हैं।[14]

एसडीजी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए और ऊर्जा सुरक्षा के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में निश्चित कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 1 मई 2016 को महिलाओं को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना शुरू की।

शोध आलेख का उद्देश्यः

इस शोध आलेख का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण की राह में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की भूमिका का अध्ययन करना और एसडीजी लक्ष्य तीन (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) एसडीजी लक्ष्य पांच (लैंगिक समानता) एसडीजी लक्ष्य सात (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) और एसडीजी लक्ष्य बारह (सतत् उपभोग और उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों के सतत् प्रबंधन) की प्राप्ति में उज्जवला योजना कितनी सहायक सिद्ध हो रही है का अध्ययन करना है।

शोध आलेख की समस्या

मानवता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन संकट का सामना कर रही है। जलवायु परिवर्तन में ऊर्जा का प्रमुख योगदान है। दुनिया की लगभग एक तिहाई जनसंख्या लकड़ी, लकड़ी का कोयला, कोयला और मिट्टी के तेल जैसे ईंधन का उपयोग करती हैं क्योंकि खाना पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन और प्रौद्योगिकियों की कमी है। भारत में महिलाएं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और निम्न आय वर्ग में, मिट्टी के चूल्हे पर भोजन पकाती हैं जिससे वह धुएं के कारण गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाती हैं। महिलाओं की यह समस्या प्रमुख है जिसके साथ विकास करना सम्भव नहीं है। मिट्टी के चूल्हे पर भोजन पकाने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कारण है। ऊर्जा दक्षता के लिए अक्षय ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि और जलवायु परिवर्तन शमन और आपदा जोखिम में कमी के लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी की आवश्यकता है।

शोध आलेख की पद्धति

प्रस्तुत शोध आलेख द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। शोध में ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक एवं विवरणात्मक शोध पद्धति का प्रयोग किया गया है।

शोध परिकल्पना

पीएम उज्जवला योजना ने एसडीजी लक्ष्य पांच, एसडीजी लक्ष्य सात और एसडीजी लक्ष्य बारह को प्राप्त करने में और महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेश की एक योजना के रूप में भारत के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और खाना पकाने में जलने वाले ईंधन के उपयोग को कम करके भारत की ऊर्जा दक्षता में सुधार किया है।

साहित्यिक पुनरावलोकन

शोध आलेख लिखने से पहले संबंधित विषय पर पूर्व प्रकाशित शोध पत्रों, आलेखों, रिपोर्ट और पुस्तकों का व्यापक रूप से अध्ययन एवं अवलोकन किया गया है।

सुभाश बी. धोंडे (2020) ने अपने शोध पत्र, 'सतत् विकास लक्ष्यः एक समीक्षात्मक विश्लेषण' में एसडीजी को रेखांकित किया है और विश्लेषण किया है कि लक्ष्य पांच स्तंभों पर कैसे आधारित हैं– लोग, समृद्धि, ग्रह, शांति और साझेदारी। भारत के संदर्भ में, शोध पत्र 2030 तक एसडीजी प्राप्त करने के महत्व पर प्रकाश डालता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जनसांख्यिकीय लाभांश का तेजी से आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए उपयोग हो।[1]

राकेश, श्रीवास्तव (2018) ने अपने लेख में 'ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरणः आगे की राह' में गामीण महिलाओं के सर्वांगीण विकास पर जोर देते हुए उनके आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण को आवष्यक बताया है। उन्होंने महिलाओं को उनकी क्षमता का अहसास कराने और अधिकारों के प्रति जागरूक कराने का सुझाव दिया। महिलाओं को समानता प्रदान करने के लिए उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी असमानताओं पर विचार व्यक्त किया।[2]

डॉ. अर्चना, शर्मा (2018) ने अपने शोध 'महिला सशक्तिकरण का आर्थिक और सामाजिक पहलू' में महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए सामाजिक और आर्थिक पहलुओं के सुदृढ़ीकरण की

बात की। क्योंकि महिलाएं देष की 50 प्रतिशत जनसंख्या का नेतृत्व करती हैं इसलिए समाज में घरेलू हिंसा मुक्त वातावरण का विकास और शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कर उनकी भागीदारी स्तर को बढ़ावा देना महिला सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है उनका मानना है कि महिलाओं को पुरुषों के समान न ही अवसर प्राप्त है और न ही सम्पत्ति में अधिकार दिया जाता है। अतः आवश्यक है कि पुरुष अपनी मानसिकता में बदलाव करें।[3]

डॉ. नीलेश, कुमार तिवारी (2020) ने अपने लेख 'ग्रामीण भारत के सतत् विकास हेतु महिला सशक्तिकरण' में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण को समाज के पारंपरिक कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों को सजगता पूर्वक सम्पन्न करने के लिए उनके सशक्तिकरण को आवष्यक बताया। ग्रामीण भारत में सतत् विकास में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रौद्योगिकी, सूचना संचार, दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार और बीमारियों से बचाव, शिक्षा कौषल विकास, रोजगार और क्षमता विकास को आवश्यक बताया है।[4]

रमन, देवी (2017) ने अपने शोध लेख 'Pradhan Mantri Ujjwala Yojana : Issues and Challenges' में विश्व स्वास्थ्य संगठन कि रिपोर्ट के आधार पर पारंपरिक ईंधन से होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभावों पर प्रकाश डाला है। इन्होंने पारम्परिक ईंधनों जैसे लकड़ी, गोबर के उपले आदि पर खाना पकाने से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को रेखांकित किया है। इस लेख के अनुसार भारत में गरीबों तक गैस पहुँचाना एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे समय की बचत होगी तथा साथ ही स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।[5]

राजनाथ, राम और शफकत, मुबारक (2018) ने अपने लेख 'प्रधानमंत्री उज्जवला योजनाः बदली ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी' में पीएम उज्जवला योजना से ग्रामीण महिलाओं को होने वाले लाभ का अध्ययन किया है। उन्होंने अपने अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि एलपीजी को भोजन पकाने के लिए सस्ते ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने से न मात्र महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है बल्कि रसोई कार्य में बचे हुए समय को उत्पादक कार्यों में लगाकर अपनी जीविका को बेहतर कर रहीं हैं।[6]

विवेक, आनंद (2018) ने अपने लेख 'Two years of Ujjwala Yojana: Dalits in western UP and benefits despite resentment against centre on other issues' में योजना के प्रभाव को रेखांकित करते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर व्यापक प्रभाव को स्वीकारा। इन्होंने अपने सर्वेक्षण के आधार पर महिलाओं की इस योजना के बारे में व्यापक चर्चा की है और निष्कर्ष निकाला है कि इस योजना से विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की निम्न आय वर्ग की महिलाओं पर लाभकारी प्रभाव पड़ा है ।[7]

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के उद्देश्यः भारत सरकार ने 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्जवला योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी वितरकों में पंजीकृत होने के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता देकर एलपीजी कवरेज के अंतर्गत लाना है। इस योजना में कहा गया है कि यह गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना 2011 में सूचीबद्ध महिलाओं) के लिए पांच करोड़ जमा–मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करेगा, और योजना में निर्दिष्ट कम से कम एक अभाव से पीड़ित हैं।

● स्वच्छ ईंधन प्रदान करना (एसडीजी लक्ष्य सात, "सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना")

● परंपरागत ईंधन के प्रयोग से होने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों को कम करना (एसडीजी लक्ष्य तीन "अच्छा स्वास्थ्य और भलाई")

● वायु प्रदूषण कम करना एवं पर्यावरण को स्वच्छ करना (एसडीजी लक्ष्य बारह, "सतत् उपभोग और उत्पादन, प्राकृतिक संसाधनों के सतत् प्रबंधन और कुषल उपयोग")

● महिला सशक्तिकरण (एसडीजी लक्ष्य पांच "लैंगिक समानता प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना")

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना – क्रियान्वयन प्रक्रिया और उपलब्धियाँः

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए 4500 से 5000 रूपये की धनराशि व्यय करना निर्धारित था, जिसे घटा कर 3,200 रू कर दिया। योजना में पंजीकृत परिवारों को एलपीजी गैस कनेक्शन के लिए आधी राशि रू 1600/– सरकार द्वारा गैस एंजेसी को अनुदान से प्राप्त होती है और पहली बार सिलेंडर भरवाने में लाभार्थियों रू 1600/– की धनराषि का भुगतान करना पडता है। सुविधा के लिए राशि को किश्तों में चुकाने की सहूलियत भी प्रदान की गई है।

सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना 2011 सर्वेक्षण के अनुसार, देश में 24.49 करोड़ (17.97 करोड़ ग्रामीण और 6.52 करोड़ षहरी) परिवार थे। इनमें से 10.31 करोड़ परिवार (8.72 करोड़ ग्रामीण और 1.59 करोड़ शहरी परिवार) थे। इस योजना के तहत् एलपीजी कनेक्शन पाने के पात्र थे क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा आवश्यक मानदंड के रूप में सूचीबद्ध कम से कम एक अभाव का सामना करना पड़ा। भारत सरकार ने इस योजना के तहत् मार्च 2020 तक पांच करोड़ एलपीजी कनेक्षन प्रदान करने का लक्ष्य रखा, जिसे फरवरी 2018 में संशोधित कर आठ करोड़ कर दिया गया। 2018[1] में 8000 करोड़ का प्रारंभिक बजट बढ़ाकर[1] 12,800 करोड़ कर दिया गया। योजना के अनुसार, पात्र बीपीएल परिवारों की महिलाएं, जो निकटतम एलपीजी वितरक के पास आवेदन करती हैं और पंजीकरण करती हैं, उन्हें एक मुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, यदि उनके घर में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं है, (एलपीजी सिलेंडर के लिए सुरक्षा जमा राशि के लिए 1600 रुपये और अन्य खर्च)। इस प्रकार यह योजना स्टोव या पहली रिफिल की लागत को कवर करके सहायता प्रदान करती है।

● सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या अप्रैल 2014 में 14.9 करोड़ से बढ़कर मार्च 2024 तक 32.42 करोड़ हो गई है।

● पीएमयूवाई योजना (उज्जवला 1.0, 2.0 और 2.0–विस्तारित) ने मई 2016 से लगभग 10. 33 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया है।

● स्थापना के बाद से पीएमयूवाई कनेक्षन का उच्चतम प्रतिषत पूर्वी क्षेत्र (32.4 प्रतिशत) में है, इसके बाद उत्तरी क्षेत्र (29.7 प्रतिशत), पष्चिमी क्षेत्र (21.5 प्रतिशत), दक्षिणी क्षेत्र (10.5 प्रतिशत) और उत्तर–पूर्व क्षेत्र (6.0 प्रतिशत) का स्थान है।[(15)]

● उज्जवला 2.0, योजना का दूसरा चरण, 10 अगस्त, 2021 को कम आय वाले परिवारों को जमा–मुक्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू किया गया जिन्हें योजना के पहले चरण के तहत कनेक्शन प्रदान किया जा सका था। इसका उद्देश्य 10 मिलियन अधिक लाभार्थियों को कनेक्शन प्रदान करना है। उज्जवला 2.0 के तहत्, प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा दी जाती है।

● योजना का विस्तार करने के लिए सरकार ने छोटे आकार (5 किलोग्राम) के सिलेंडर शुरू किए, ताकि रिफिल की एक बार की उच्च लागत की चुनौती को कम किया जा सके।

● दिसंबर 2022 में, प्रवासी परिवारों को विशेष सुविधा के साथ, 1.6 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन किया गया, जिससे योजना के तहत् कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 9.6 करोड़ हो गई।

● योजना 2022 (चरण 1) के तहत् एलपीजी कनेक्शन 79.8 और चरण 2 में 13.5 करोड़ है।

● सितंबर 2023 में उज्जवला योजना के विस्तार को मंजूरी दी, ताकि 3 वर्षों (2023–24 से 2025–26) में 75 लाख अतिरिक्त एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा सकें। इससे पीएमयूवाई लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी।[16]

स्कीम के कार्यान्वयन के बाद कनेक्शनों की संख्या में वृद्धि तालिका 1 में दर्शाई गई है। (परिशिष्ट – 1)

● एलपीजी कनेक्शन वाले मौजूदा बीपीएल परिवारों की खपत 3–4 रीफिल प्रति वर्ष है।

● वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान लाभार्थियों द्वारा खपत रिफिल की संख्या – 31.47 करोड़ थी । तालिका दो सब्सिडी के रूप में योजना पर व्यय को दर्शाती है। (परिशिष्ट – 2)

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के कारण महिला सषक्तिकरण और कल्याणः

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन प्रदान करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना था। ताकि सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल किया जा सके यह योजना निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रही है :

● खाना पकाने में लगने वाले समय को रोजाना 1–2 घंटे कम करने में मदद मिली है। खाना पकाने के समय में कमी मुख्य रूप से गैस स्टोव पर तेजी से खाना पकाने और जलाऊ लकड़ी आदि के संग्रह में पहले उपयोग किए जाने वाले समय की बचत के कारण है।

● खाना पकाने के बर्तन धोने में लगने वाले समय में कमी के कारण भी महिलाओं को लाभ हुआ है क्योंकि बर्तन दाग मुक्त होते हैं।

● एलपीजी का उपयोग करते समय मिट्टी के चूल्हे पर भोजन पकाने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी आई है। अब उनके घर धुआं रहित हैं और स्वच्छ हैं।

● पारंपरिक खाना पकाने से धुएं के कारण समस्याएं जो महिलाओं को झेलनी पड़ती थीं जैसे आंखों में जलन, खांसी आदि में काफी हद तक गिरावट आई है।[17]

चुनौतियाँ

आंकड़ों से पता चलता है कि योजना के लागू होने के बाद एलपीजी कनेक्शन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। लेकिन औसत गैस सिलेंडर की रिफिलिंग दर में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाती

है। 2016–17 में औसत गैस सिलेंडर की रिफिलिंग दर 3.9 थी और 2018–19 में घटकर 2.98 हो गई। वार्षिक रिफिल दर प्रति केवल तीन से चार सिलेंडर है। एलपीजी रीफिल की अधिक कीमत और पारम्परिक ईंधन (जलावन की लकड़ी, गाय के गोबर की खली आदि) की आसान/निशुल्क उपलब्धता के कारण लाभार्थियों ने अशुद्ध ईंधन नीतियों का उपयोग करना पुनः शुरू कर दिया है। अक्सर महिलाएं अपने एलपीजी स्टोव का उपयोग प्रतिदिन केवल एक बार खाना पकाने के लिए करती हैं ताकि इसे बचाया जा सके।[18]

एलपीजी सिलेंडरों की रिफिल में गिरावट का एक और कारण यह है कि परिवार के पास दो सिलेंडर नहीं होते हैं यानी सिलेंडर खाली होने से पहले रिफिल बुक करने के लिए ।
ग्रामीण क्षेत्रों और दूर–दराज के क्षेत्रों में पर्याप्त वितरकों की कमी के कारण रीफिल की आपूर्ति में विलंब होता है। अकसर आपूर्ति लाभार्थियों के घरों पर नहीं की जाती है और उन्हें इसे वितरकों से एकत्र करना होता है।

सरकार को भी योजना के क्रियान्वयन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती प्रामाणिक आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण मुफ्त एलपीजी कनेक्शन के आवंटन के लिए गरीब घरेलू महिलाओं की पहचान करना है।

निष्कर्षः

सरकार को चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और ईंधन सब्सिडी बढ़ाने, वितरण प्रणाली में सुधार, नई सस्ती खाना पकाने की तकनीक और उपकरणों की आपूर्ति जैसे उपाय करने चाहिए और विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की जरूरतों के लिए विशिष्ट उपायों को पेश करना चाहिए। अंत में, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान लाभार्थियों के नामांकन को बढ़ाने में एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। यदि ग्रीन गैस उत्सर्जन के कारण पर्यावरणीय क्षरण के मुद्दों को नजरअंदाज किया जाता है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर प्रभाव अंततः नकारात्मक होगा। सशक्तिकरण, सामाजिक समावेश और निष्पक्ष और न्यायसंगत आर्थिक प्रगति सतत् विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पीएम उज्जवला योजना के सफल कार्यान्वयन से निश्चित रूप से सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलेगी।

सन्द्रर्भ

1. सुभाष बी. धोंडे. (2020) सतत् विकास लक्ष्यः एक समीक्षात्मक विश्लेषण. International Journal of Hindi Research. 6(4), 15-19.
2. श्रीवास्तव, राकेश. (2018) ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरणः आगे की राह कुरूक्षेत्र, मासिक अंक 3, जनवरी 2018 पृ0 **5–11**
3. शर्मा, डॉ. अर्चना. (2018) महिला सशक्तिकरण का आर्थिक और सामाजिक पहलू, कुरूक्षेत्र, मासिक अंक 3, जनवरी 2018, पृ0 **58–62**
4. तिवारी, कुमार, डॉ. नीलेश. (2020) ग्रामीण भारत के सतत् विकास हेतु महिला सशक्तिकरण, कुरूक्षेत्र, मासिक अंक 7, जनवरी 2020, पृ0 **22–26**

4. Devi Raman. (Sep. 2017). "Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: Issues and challenges." International Journal of Academic Research and Development. 2(5) 705-706 https://www.multidisciplinaryjournal.in/assets/archives/2017/vol2issue5/2-5-487-314.pdf
5. राजनाथ, राम और षफकत, मुबारक. (2018). प्रधानमंत्री उज्जवला योजनाः बदली ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी, कुरूक्षेत्र मासिक अंक 3, जनवरी 2018, पृश्ठ 24–26
6. Anand, V, (28 May 2018). Two years of Ujjwala Yojna: Dalits in Western U.P. Land Benefits, Resentment against Centre on Other Issues. First Post. https://www.firstpost.com/india/two-years-of-ujjwala-yojana-dalits-in-western-up-laud-benefits-despite-resentment-against-centre-on-other-issues-4481319.html
7. UNEP. SDG 7: Ensure Access to Affordable, Reliable, Sustainable and Modern Energy for All https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals/why-do-sustainable-development-goals-matter/goal-7
8. UNEP. UNEP and the Sustainable Development Goals, Why the SDGs Matter https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals
9. United Nations Environment Programme (UNEP). GOAL 7: Affordable and Clean Energy, https://www.unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals
10. WHO. 15 Dec 2023. Household air pollution. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/household-air-pollution-and-health
11. United Nations. 2015. Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development.https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld/publication
12. United Nations. 2021. Global Roadmap for Accelerated SDG7 Action in Support of the 2030 Agenda for Sustainable Development and the Paris Agreement on Climate Change. https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/11/hlde_outcome_sdg7_global_roadmap.pdf
13. N. Ahmad, Sharma, S. et al. (2018). Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) Step towards Social Inclusion in India. International Journal of Trend in Research and Development, Vol. 5(1). 46-49. https://www.researchgate.net/publication/342804302_Pradhan_Mantri_Ujjwala_Yojana_PMUY_Step_towards_Social_Inclusion_in_India
14. GOI. 11 Dec 2019. Ministry of Petroleum and Natural Gas. Report of the Comptroller and Auditor General of India on Pradhan Mantri Ujjwala Yojana.https://cag.gov.in/en/audit-report/details/55961#:~:text

15. GOI. Ministry of Petroleum and Natural Gas. LPG Profile Report [FY 2023-24] https://ppac.gov.in/download.php?file=rep_studies/1716870573_LPG_Profile_Report_FY_2023-24-Web.pdf
16. वर्मा, सुनील कुमार. प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सषक्तिकरण पर प्रभाव का अध्ययन, International Journal of Creative and Research Thoughts 8(11), Nov. 2020 pg. 3589-3592. https://www.researchgate.net/publication/358088818_Pradhan_Mantri_Ujjwala_Yojana_Ka_Mahiaon_Ke_Swasthya_avam_Sashaktikaran_Par_Prabhav_Ka_Adhyyan
17. Business Standards. (24 Jan 2020). "Ujjwala Scheme Provided LPG Access, but Failed to Promote its Use Study." https://www.business-standard.com/article/pti-stories/india-s-ujjwala-scheme-provided-lpg-access-but-failed-to-promote-its-use-study-120012400603_1.html
18. Jain Abhishek, Poulami Choudhary and Karthik Ganesan (Feb. 2015) "Clean Affordable and Sustainable Cooking energy for India - Possibilities and Realities Beyond LPG." Down to Earth. https://www.downtoearth.org.in/energy/india-steps-on-the-gas-58502#:~:text